

विक्रांत की नही यह तो देश के गौरव की नीलामी : राम नाईक

मुंबई, बुधवार: “कांग्रेस सरकार विक्रांत की नही तो इस देश के गौरव और अस्मिता की ही नीलामी करना चाहती है. देश की रक्षा में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाला ‘विक्रांत’ मात्र युद्ध पोत नही, तो देश के सम्मान का प्रतिक है. इसिलिए उसकी नीलामी की बातें दुःखद तथा क्रोध पैदा करनेवाली है”, ऐसी प्रतिक्रिया पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक ने दी. 31 जनवरी 1997 को विक्रांत को सेवा मुक्त करने के निर्णय की रक्षा मंत्रालय ने घोषणा करते ही उसका ‘संग्रहालय’ बनाया जाए ऐसी माँग करने वाले तथा वह पुरी करवाने में कामयाब रहे श्री. नाईक आज 15 वर्ष बाद हो रही नीलामी की भाषा से काफी क्रोधित हुए हैं. आज एक प्रेस विज्ञप्तीद्वारा श्री. नाईक ने अपना क्रोध व्यक्त किया.

लोकसभा में 21 मार्च 1997 को ‘विशेष वक्तव्य’ के माध्यम से सबसे पहले श्री. राम नाईक ने यह मुद्दा उठाया था. 14 लडाईयों में हिस्सा लेकर स्वतंत्रता के बाद ‘देशभक्ती तथा वीरता का प्रतिक’ बने विक्रांत को संरक्षित रखा जाए ऐसी माँग तब श्री. नाईक ने की थी. इस माँग को पुरा करवाने के लिए उन्होने लगातार प्रयास भी किये. 1999 में केंद्र में वाजपेयी सरकार ने विक्रांत को बन्दरगाह में सुखी जगह पर ‘स्मारक’ के रूप में रखने का निर्णय किया. बाद में सत्ता में आयी कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण इस स्मारक को बनाए रखने के खर्चे में काफी वृद्धी हो गयी. “फिर भी अभी इसकी रक्षा की जा सकती है. हिंदुस्थान में समुद्र में रक्षा केंद्र बनाने की दूरदर्शिता रखनेवाले राजा शिवाजी की परंपरा महाराष्ट्र ने कायम रखनी चाहिए. इस गरिमा को भंग करने की गलती अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण करेंगे तो न जनता उन्हें क्षमा करेगी, न इतिहास!”, ऐसी टीपणी भी अंत में श्री. राम नाईक ने की.

(कार्यालय मंत्री)